

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR)

प्रलिमिस के लिये:

महिलाओं के खलिफ सभी प्रकार के भेदभाव के उनमूलन पर कन्वेशन (CEDAW), नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR), बीजगि घोषणा-पत्र एवं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय कशीर स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2030 एजेंडा।

मेन्स के लिये:

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR) : SRHR के उल्लंघन का कारण और परणाम, भारत में SRHR की आवश्यकता, SRHR से संबंधित पहल, SRHR सुनिश्चित करने के लिये उठाए जाने वाले कदम।

प्रसंग क्या है?

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (Ensuring Sexual and Reproductive Health Rights- SRHR) सुनिश्चित करना विश्व भर में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के समार स्वास्थ्य, कल्याण एवं सामाजिक-आरथक विकास के लिये सर्वोपराहै। SRHR में नविश करने हेतु सरकारों को प्रतिबिध करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बावजूद, राजनीतिक दृढ़ संकल्प की कमी, अपर्याप्त धन, लगातार लैंगिक असमानता व कामुकता से जुड़े मुद्दों का खुलकर सामना करने की अनियिछा के कारण प्रगति बाधित हुई है।

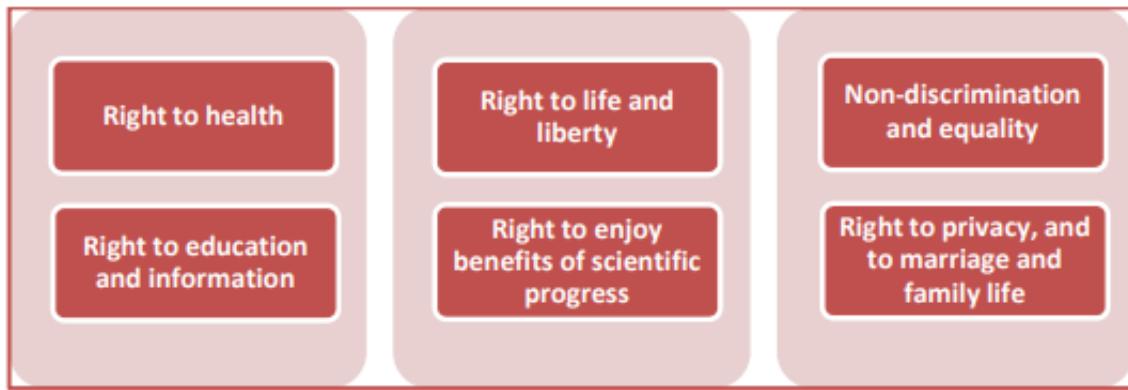
यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार क्या हैं?

परचियः

- SRHR में यौन और प्रजनन से संबंधित मानवाधिकारों का एक स्पेक्ट्रम शामिल है। इन अधिकारों में नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आरथक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं एवं पुरुषों दोनों को इष्टतम यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तक समान पहुँच प्राप्त हो।
 - इसमें भेदभाव, अवपीड़न (Coercion) या हसिं का सामना किये बना, परिवार नियोजन सहित उनके यौन और प्रजनन जीवन के बारे में सूचति निरिण्य लेने का अधिकार शामिल है।
 - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, "प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा व्यक्तिकी सुरक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल एवं सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं के लिये संसाधनों के आवंटन व उनकी उपलब्धता और गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच का अधिकार शामिल है।"
- SRHR बच्चों और कशीरों सहित सभी व्यक्तियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हैं, तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने हेतु अभनिन अंग हैं, जिसमें न केवल बीमारी की रोकथाम बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक आयामों तक समग्र कल्याण भी शामिल है।

SRHR के संदिधांतः

- यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की उपलब्धियौन और प्रजनन अधिकारों की प्राप्ति पर निर्भर करती है, जो सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों पर आधारित हैं:
 - उनकी दैहिक अखंडता, गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान किया जाए;
 - यौन अभिनियास और लगि पहचान तथा अभिव्यक्ति सहित उनकी कामुकता को स्वतंत्र रूप से परभाषित करना;
 - तय करना कि यौन रूप से कब सक्रिय होना है या नहीं;
 - अपना यौन साथी चुनना;
 - सुरक्षति और आनंददायक यौन अनुभव प्राप्त करना;
 - तय करना कि किया, कब और कसिसे शादी करनी है;
 - निरिण्य लेना कि किया, कब और कसिसि माध्यम से बच्चा पैदा करना है या बच्चे पैदा करने हैं तथा कतिने बच्चे पैदा करने हैं;
 - उपरोक्त सभी को प्राप्त करने के लिये आवश्यक जानकारी, संसाधनों, सेवाओं और समर्थन तक उनके जीवनकाल में भेदभाव, जबरदस्ती, शोषण तथा हसिं से मुक्त पहुँच हो।



नोट:

- पुट्टास्वामी नरिण्य ने वशिष्ठ रूप से भारतीय संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हस्तिके रूप में प्रजनन वकिलप चुनने के महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को मान्यता दी।

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR) के उल्लंघन के कारण और परणिम क्या हैं?

कारण	नतीजे
महिलाओं के SRHR का उल्लंघन	<ul style="list-style-type: none"> गर्भनिरीधक, प्रसव पूर्व देखभाल और सुरक्षित गर्भपात सहित आवश्यक प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पर प्रतिबंध, अनपेक्षित गर्भधारण तथा असुरक्षित गर्भपात की दरों में वृद्धि में योगदान देता है, जिससे मातृ मृत्यु दर और सुगण्टा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अपने शरीर पर महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करने वाले सामाजिक मानदंड लगि-आधारित हस्तिको कायम रखते हैं, जिससे भय और असुरक्षा का माहौल बनता है जो शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्रभावित करता है।
पत्रिसत्तात्मक मान्यताएँ और सामाजिक मूल्य	<ul style="list-style-type: none"> पत्रिसत्तात्मक वयवस्था और परांपराकि सामाजिक मूल्य उन रूद्धियों तथा मानदंडों को मजबूत करके लैंगिक असमानता को कायम रखते हैं जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों की भूमिकाओं एवं योगदान को प्राथमिकता देते हैं। <ul style="list-style-type: none"> यह अवमूल्यन प्रजनन से परे तक फैला हुआ है, महिलाओं की शिक्षा, रोज़गार के अवसरों और नरिण्य लेने की प्रक्रियाओं तक पहुँच को सीमित करता है तथा उन्हें सामाजिक कलंक, भेदभाव और हाशयि पर डाल देता है।
शीघ्र विवाह और गर्भावस्था	<ul style="list-style-type: none"> कम उम्र में विवाह जैसी सांस्कृतिक प्रथाएँ लड़कियों को स्वायत्तता और शक्षिा से वंचित करती हैं, जिससे जल्दी तथा बार-बार गर्भधारण होता है। <ul style="list-style-type: none"> कशिर गर्भधारण से मातृ जटिलियों का खतरा बढ़ जाता है और गरीबी एवं निर्भरता का चक्र बना रहता है क्योंकि युवा माताओं को अक्सर शक्षिा तथा रोज़गार में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य व सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और बढ़ जाती हैं।
मातृ मृत्यु दर और सुगण्टा	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षित गर्भपात सेवाओं और कुशल मातृ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक सीमित पहुँच के परणिमस्वरूप मातृ मृत्यु दर और सुगण्टा की उच्च दर देखी जाती है। <ul style="list-style-type: none"> पहुँच की यह कमी मौजूदा चुनौतियों को बढ़ाती है, जो मातृ मृत्यु, जटिलियों और वशिष्ठ रूप से सीमित स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों वाले हाशयि पर रहे स्थिति समुदायों में महिलाओं तथा उनके परवारों के लिये दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव में योगदान देती हैं।

भारत में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR) की क्या आवश्यकता है?

- महलियों की स्वायत्तता और प्रजनन स्वास्थ्य के लिये चुनौतियाँ: कई महलियों में शारीरक स्वायत्तता का अभाव बना हुआ है। नवीनतम राष्ट्रीय प्रविवर स्वास्थ्य संरचना (NFHS-5) के अनुसार, भारत में केवल 10% महलियों स्वतंत्र रूप से अपने स्वास्थ्य के बारे में निरण्य लेने में सक्षम हैं और 11% महलियों का मानना है कि विद्युतीय महलि अपने पति के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करती है तो उन्हें वैवाहिक हस्ति का सामना करना पड़ता है। भारत में लगभग आधे ग्रन्थाधारण अनियोजित होते हैं।
- असुरक्षित ग्रन्थाधारण का उच्च प्रसार: भारत में 15 मलियन ग्रन्थाधारण में से लगभग 78% का कारण चकितिसा सुविधायों का उपलब्ध न होना है, जो महत्वपूर्ण सुरक्षित ग्रन्थाधारण सेवाओं तक पहुँच की कमी को दर्शाता है।
- ग्रन्थाधारण का उच्च प्रसार: भारत के प्रजनन वर्षों में 30 मलियन से अधिक विवाहित महलियों ग्रन्थाधारण का उपयोग करने में असमर्थ हैं, जो प्रविवर नियोजन सेवाओं में बाधायों को उजागर करता है।
- कशियों पर प्रजनन स्वास्थ्य चुनौतियाँ: भारत में 2 मलियन कशियों में आधुनिक ग्रन्थाधारण तक पहुँच नहीं है और जन्म देने वाली कशियों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत का अनुशंसित न्यूनतम चार प्रसव-पूर्व देखभाल परीक्षण में शामिल न होना है।
- जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार का ध्यान: प्रजनन अधिकारों के लिये सरकार के ऐतिहासिक दृष्टिकोण ने व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यापक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पर जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता दी है, जिससे ग्रन्थाधारण एवं ग्रन्थाधारण का सार्वभौमिक पहुँच जैसी पहल पर ध्यान केंद्रित करने में कमी देखी गई है।
- लगि आधारति हस्ति का हाशियाकरण: भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में लगि आधारति हस्ति को अक्सर हाशिया पर रखा जाता है, जिसे मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी चतियों के बजाय कानून-व्यवस्था के मुद्दे के रूप में संबोधित किया जाता है, बावजूद इसके क्षेत्रियों की भर्ताई पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।
- असुरक्षित ग्रन्थाधारण के कारण मातृ मृत्यु: [संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष \(UNFPA\)](#) की विश्व जनसंख्या रपोर्ट 2022 के अनुसार, असुरक्षित ग्रन्थाधारण के कारण मातृ मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है तथा प्रतिवर्ष असुरक्षित ग्रन्थाधारण से संबंधित कारणों की वज़ह से लगभग 8 महलियों की मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2007-2011 के बीच भारत में 67% ग्रन्थाधारण के मामलों को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR) से संबंधित पहल क्या हैं?

- वैश्वकि पहल:
 - महलियों के विद्युतीय सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW): यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन है जिसके लिये देशों को सभी क्षेत्रों में महलियों और लड़कियों के खलिफ भेदभाव को खत्म करना होगा तथा महलियों एवं लड़कियों के समान अधिकारों को बढ़ावा देना होगा।
 - CEDAW को अक्सर महलियों के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बलि के रूप में वर्णित किया जाता है और यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक है जो लैंगिक समानता हासिल करने तथा सभी महलियों और लड़कियों को सशक्त बनाने में मार्गदरशन करता है।
 - [नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध \(ICCPR\)](#): इसका उद्देश्य नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिनमें शामिल हैं:
 - भेदभाव से मुक्ति, पुरुषों और महलियों के बीच समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, प्रताङ्गना/यातना से मुक्ति, दासता से मुक्ति, व्यक्तिकी स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, हरिसत में मानवता का व्यवहार करने का अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, गैर-नागरिकों को मनमाने निषिकासन से मुक्ति, निषिपक्ष सुनवाई का अधिकार, कानून के समक्ष मानवता का अधिकार, निजिता का अधिकार, धर्म और वशिवास की स्वतंत्रता, अभियांत्रिकी की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, विवाह करने और प्रविवर बसाने का अधिकार, बच्चों का जन्म पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता का अधिकार, सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार।
 - बीजगी घोषणा-पत्र एवं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन: यह महलियों के सशक्तीकरण के लिये एक दूरदर्शी एजेंडा है। यह विश्व भर में महलियों की स्थितिका विश्लेषण करने और महलि सशक्तीकरण के समर्थन में राज्यों के प्रयासों का आकलन करने हेतु संदर्भ ढाँचे में से एक है।
- राष्ट्रीय पहल:
 - ग्रन्थाधारण का वसितार और सुदृढ़ीकरण: [प्रविवर नियोजन 2030 साझेदारी](#) के प्रति भारत की प्रतिबिद्धता में अपनी ग्रन्थाधारण बास्केट (Contraceptive Basket) का वसितार करना शामिल है। नए ग्रन्थाधारण वकिलों को शामिल करने से महलियों के अधिकारों और स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है, जिससे आधुनिक ग्रन्थाधारण के प्रचलन में वृद्धि होती है।
 - समय पर गुणवत्तापूर्ण और कफियती प्रविवर नियोजन सेवाओं तक पहुँच महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना अंतराल के ग्रन्थाधारण से नवजात शशि के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही मातृ मृत्यु दर, उण्ठना तथा स्वास्थ्य देखभाल व्यय पर बढ़ा प्रभाव पड़ सकता है।
 - [भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017](#): यह मौजूदा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से प्रजनन, मातृ, बाल और कशियों स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के लिये नशिलक, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देती है।
 - इसके अलावा भारत सरकार ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिये प्रदाता आधार का वसितार करने हेतु देश भर में [प्रसूति विद्या](#) सेवाएँ भी शुरू की हैं।
 - [राष्ट्रीय कशियों स्वास्थ्य कार्यक्रम \(RKSK\)](#): वर्ष 2014 में शुरू की गई यह पहल कशियोंवास्था के दौरान स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देने, युवा लोगों की विशिष्ट यौन और प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करने पर केंद्रित है।
 - कशियों यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में कमयों को दूर करना: प्रगति के बावजूद महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें सटीक जानकारी तक सीमित पहुँच और व्यापक ग्रन्थाधारण देखभाल शामिल है। प्रदाता पूर्वाग्रह और अपर्याप्त जानकारी जैसी बाधायों को दूर करने के लिये प्रयासों की आवश्यकता है।
 - [SDG में SRHR के प्रति भारत की प्रतिबिद्धता](#): [सतत विकास लक्षण \(SDG\)](#) में SRHR का एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय नीति ढाँचे में इसकी मानवता इन अधिकारों को बनाए रखने का करतवय राष्ट्रों पर है और यह मौलिक मानवाधिकारों के रूप में यौन एवं प्रजनन

स्वास्थ्य की स्वीकृतिको अनविराय बनाती है।

- सतत विकास के लिये 2030 एजेंडा पर हस्ताक्षरकर्त्ता और वैश्वकि आबादी के एक महत्वपूर्ण हस्तियों के घर के रूप में भारत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों और कानून के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये मजबूर है।
- स्वास्थ्य पर SDG 3 और लैंगिक समानता तथा महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण पर SDG 5 दोनों में यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारों से संबंधित लक्ष्य शामिल हैं।

नोट: भारत सरकार के स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास कार्यक्रमों ने पछिले कुछ वर्षों में लगातार प्रगतिदिखाई है। पछिले कुछ वर्षों में भारत में जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- 1990 के दशक की तुलना में वर्तमान में एक भारतीय की जीवन प्रत्याशा में एक दशक से अधिक समय की वृद्धि हुई है। मातृ स्वास्थ्य के मामले में भारत ने प्रभावशाली प्रगति की है। मातृ मृत्यु दर की वर्तमान दर 97 (प्रति 100,000 जीवति जनसंख्या) है, जो वर्ष 2004 में 254 से कम है।
- इन कार्यक्रमों की एक और जीत लैंगिक सशक्तीकरण है। वर्ष 2000 की शुरुआत से भारत में बाल विवाह की संख्या आधी हो गई है।
 - कशीर ग्रन्थधारण में भी उल्लेखनीय कमी आई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण सहित महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच में भी सुधार हुआ है।

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR) सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- व्यापक लैंगिक शिक्षा (CSE): स्कूलों और समुदायों में आमु-उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तथा साक्ष्य-आधारित यौन शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने से व्यक्तियों को यौन स्वास्थ्य, रशिते, ग्रन्थधारण तथा सहमति के बारे में सटीक जानकारी मिल सकती है।
 - **संवर्द्धित वास्तवकिता (Augmented Reality- AR)** और **आभासी वास्तवकिता (Virtual Reality- VR)** प्रौद्योगिकियों मासिक धरम स्वास्थ्य शिक्षा को व्यापक एवं इंटरैक्टिव शिक्षण अनुभव बना सकती है।
- ग्रन्थधारक और परवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच: कफियती और सुलभ ग्रन्थधारक तथा परवार नियोजन सेवाएँ सुनिश्चित करने से व्यक्तियों को अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित विकलिप चुनने एवं अनपेक्षित ग्रन्थधारण को रोकने की अनुमति मिलती है।
- सुरक्षित एवं कानूनी ग्रन्थपात सेवाएँ: सुरक्षित और कानूनी ग्रन्थपात सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने से व्यक्तियों के प्रजनन अधिकारों की रक्षा हो सकती है तथा स्वास्थ्य एवं जीवन को खतरे में डालने वाली असुरक्षित ग्रन्थपात प्रथाओं को रोका जा सकता है।
- स्वास्थ्य कार्यबल क्षमता: समय पर उच्च-गुणवत्ता और सम्मानजनक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता एवं कौशल को बढ़ाना आवश्यक है।
- अंतर-क्षेत्रीय सहयोग: यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिये पूरे जीवन चक्र में पहुँच तथा समर्थन सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा व परविहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता होती है।
- लक्षित निविश की आवश्यकता: भारत के लिये गुटमाकर-लैंसेट आयोग की सफिरशियों के अनुसार, अवांछित ग्रन्थधारण, असुरक्षित ग्रन्थपात, अनियोजित प्रसव और मातृ मृत्यु दर को कम करने के साथ-साथ युवा लोगों की शारीरिक स्वायत्तता तथा कल्याण की सुरक्षा के लिये कशीर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य में लक्षित निविश महत्वपूर्ण है।
- समुदाय-आधारित सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम: नवीन सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को शामिल करने से मासिक धरम के आसपास की चुप्पी और कलंक (Silence and Stigma) को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ये कार्यक्रम महिलाओं तथा लड़कियों को मासिक धरम स्वच्छता दूत (Menstrual Hygiene Ambassadors) बनाने के लिये प्रशिक्षित कर सशक्त बना सकते हैं।

निषिकरण

भारत में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (SRHR) सुनिश्चित करने की दिशा में यात्रा जारी है, जिसमें प्रगतिके साथ-साथ लगातार चुनौतियों भी सामने आ रही हैं। जैसे-जैसे हम लैंगिक समानता, स्वास्थ्य देखभाल पहुँच तथा सामाजिक मानदंडों की जटिलियों से निपटते हैं, सभी के लिये स्वायत्तता, गरमि एवं कल्याण को बढ़ावा देने हेतु हमारी प्रतिबिधिता को दृढ़ करना आवश्यक है। समावेशिति, शिक्षा व सहयोगात्मक प्रयोगों को अपनाकर, हम एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और एक सहायक तथा न्यायसंगत समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है।

UPSC सविलि सेवा, विगत वर्ष के प्रश्न

?????????????????

प्रश्न. प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला 'बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच (बीजिंग डिक्लिरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन)' निम्नलिखित में से क्या है? (2015)

- (a) क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति (स्ट्रैटेजी), शांघाई सहयोग संगठन की बैठक का एक प्रणाली।
- (b) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आरथिक संवृद्धिकी एक कार्य-योजना, एशिया-प्रशांत आरथिक मंच (एशिया-पैसफिक इकोनॉमिक फोरम) के विचार-विमर्श का एक प्रणाली।

- (c) महलिया सशक्तीकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वशिव सम्मेलन का एक परणिमाम।
(d) वन्यजीवों के दुरव्यापार (ट्रैफिकिंग) की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शहिर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट) की एक उद्घोषणा।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. समय और स्थान के विपरीत भारत में महलियों के लिये नरितर चुनौतियाँ क्या हैं? (2019)

प्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, वशिष्ठकर जराचकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और प्रयाप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विचारना कीजिये। (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sexual-and-reproductive-health-rights-srhr->

